Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2018 = 6.371, www.srjis.com
PEER REVIEWED JOURNAL, SEPT-OCT, 2018, VOL- 6/47

उच्च शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य

श्रीमती गीता सिंह, Ph. D.

एसोसिएट प्रोफेसर(बी0एड0), डी0वी०यन0पी0जी0 कालेज, गोरखपुर

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रत्येक स्तर की शिक्षा व्यवस्था की अपनी विलक्षणताएं (एवं समस्याएं होती है। आज वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व सन्दर्भ में विलक्षणताओं एवं समस्याओं में एक नयी आकृति, दशा व गति प्राप्त हो रही है। हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था इसका अपवाद नहीं है हमारे देश में प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक संस्थाओं का संख्यात्मक दृष्टि से जिस द्रुत गति से विकास हुआ है, इसकी वजह से गुणवत्तापरक शिक्षा एवं शिक्षण उपलब्ध कराने के प्रति नया आयाम विकसित हुआ है, जिसे कोई भी जागरूक राष्ट्र नजर अन्दाज नहीं कर सकेता। यह बात संख्यात्मक वृद्धि बनाम गुणंवत्ता का नहीं बल्कि गुणवत्ता पूर्ण सर्वसुलभ शिक्षा व्यवरंथा निर्माण का है।

प्रत्येक देश की शिक्षा व्यवस्था में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसका घनिष्ठ सम्बन्ध समाज एवं राष्ट्र के चरित्र, उसकी संस्कृति व सभ्यता से होता है। इक्कीसवीं सदी में विकासशील प्रौद्योगिकी विशेष रूप से सूचना तकनीकी के परिवेश में उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी काफी बढ़ गयी है तथा लोगों की अपेक्षाएं भी उच्च शिक्षा से बढ़ी है, क्योंकि वर्तमान भौक्षिक परिवेश में काफी परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन के दौर में अपनी पहचान बनाने की आवश्यकता हैं, यही कारण है कि 2010 तक भारतीय समाज को नॉलेज सुपर पावर के रूप में अपनी पहचान बनाने के संकल्प की दिशा में भावी शिक्षा, व्यवस्था को उपयुक्त स्वरूप, प्रदान करने की अपेक्षा है।

इस सन्दर्भ में उच्च शिक्षा को नवीन परिप्रेक्ष्य में रखते हुए उसे सार्थक भूमिका निर्वहन की जिम्मेदारी लेनी होगी जिससे शिक्षा की प्रक्रिया में व्याप्त दोषों पर रोक लगायी जा सके तथा देश व समाज को एक नयी दिशा दी जा सके।

अब तक हमारे देश को आजादी मिले लगभग 70 वर्ष पूरे होने, जा रहे हैं. और हम पहले से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था को जारी रखे हुए हैं जिसका परिणाम हमारे सामने दिखायी दे रहा है। स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी हम अपने देश को सशक्त कल्पनाशील एवं. प्रभावी शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पाये हैं जो हमारे अक्षमता का द्योतक है. एवं विकास के मार्ग की–बहुत बड़ी बाधा है। शिक्षा के सभी स्तरों में विसंगतियां व्याप्त हैं। हमारी उच्च शिक्षा भी इससे अछूती नहीं है यह वर्तमान आवश्यकताओं तथा जनाकांक्षाओं के कसौटी पर खरी नहीं उतर पा रही है, जिससे यह अपनी कहीं भी सुदृढ़ पहचान

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

बनाने में अक्षम प्रतीत हो रही है। हमारी उच्च शिक्षा न तो वर्तमान आवश्यकता एबं अपेक्षा को पूरी कर रही है और न ही अपने प्राचीन मूल्यों को संरक्षित व संबर्धित करने में सफल है। इसमे प्राचीन भारतीय धारणा "वसु सुधैव कुटुम्बकम की भावना भी विलुप्त होती नजर आ रही है, परिणाम यह है कि शिक्षित व्यक्तियों की एक भीड़ तो तैयार हो रही है, परन्तु उनमें किसी प्रकार की प्रतिबद्धता व उत्तरदायित्व की भावना विकसित नहीं हो रहीं इस प्रकार उच्च शिक्षित व्यक्ति डिग्री प्राप्त करके इधर–उधर भटक रहे हैं और उनका यह भटकाव उन्हें गलत दिशा की ओर उन्मुख कर रहा है। अतः यह कहना गलत नहीं है कि उच्च शिक्षा अपने दायित्वों से हटती जा रही है तथा छात्रों में में अपेक्षित दायित्व एवं मूल्य बोध विकसित करने में असफल दिखायी दे रही है। उच्च शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता दिखायी दे रहा है। यह छात्रों में परावलम्बन की भावना को बढ़ा रही है। जिसका कारण है कि आज पढ़ा लिखा नवयुवक श्रम के प्रति अनास्था व्यक्त कर रहा है। विशेषकर स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षित व्यक्ति को यदि कहीं रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा है तो वह अपने शक्ति व समय को अनर्गल कार्यो में लगा रहे हैं जिसका खामियाजा समाज व राष्ट्र को भुगतान पड़ रहा है। वे यद्यपि हमारे देश में 23–24 वर्ष वर्ग मे केवल 6–7 प्रतिशत लोग ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं फिर भी शिक्षित बेरोजगारों की संख्या निरन्तर बढ़ती दिखायी दे रही है। इसका कारण यह है कि उच्च शिक्षा जीवन कौशलों एवं मूल्यों के संवर्धन से विमुख होकर जीवन यापन के लिए व्यवसायोन्मुख (Job Oriented) पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है। कुल मिलाकर यह कहना उचित ही है कि हमारी उच्च शिक्षा की सार्थकता सन्देह के घेरे में सिमट गयी है। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है।

(1) **जनसामान्य की पहुंच से बाहर**– नई शिक्षा नीति के तर्कों को सरकार प्रभावशाली ढंग से देखने लगी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) का यह तर्क हैं कि .शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने तथा नई सूचना तकनीकी से सम्पन्न बनाने हेतु पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता है इसकी व्यवस्था करना सरकार के बस की वात्त नहीं है अतः अन्य स्रोतों से धन जुटाने की आवश्यकता है। इसी संकंट के बहाने यू0जी०सी0 ने शिक्षा वजट में 35 प्रतिशत की कटौती की ओर विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया कि वे अपने खर्च स्वयं वहन करें। इस प्रकार शैक्षणिक व्यय को शिक्षण शुल्क के रूप में छात्रों से वसूलने का निश्चय किया गया। फलस्वरूप उच्च शिक्षा मध्यम व निम्न वर्ग के पहुंच से बाहर हो गयी। भारतीय विश्वधिद्यालय संघ के अध्यक्ष के अनुसार 30 प्रतिशत से कम छात्र ही बढ़ी हुई फीस दे सकते हैं। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा से संबंधित आयु वर्ग के 5–6 प्रतिशत युवक–युवतियां अपने देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाते हैं। इस प्रकार योग्य युवक–युवती इससे वंचित रह जाते हैं। जिससे उनमें निराशा व कुण्ठा उत्पन्न होती है।

(2) स्ववित्त पोषित संस्थाओं की वृद्धि– विश्वविद्यालय एवं वित्तपोषित संस्थाओं में सीटों को सीमित करने के कारण स्ववित्त पोषित संस्थाओं के खुलने की संभावना बढ़ गयी है। मांग के अनुरूप

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में भी स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं तथा छात्रों से 40 हजार से लेकर 60 हजार तथा कहीं–कहीं लाखों रूपये वसूल किए जा रहे हैं । धन का यह आकर्षण स्ववित्त पोषित संस्थाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। यही कारण है कि शिक्षण संस्थाओं को व्यावसायिक दृष्टि से देखा जा रहा है। ये संस्थाएं अनेक मास्टर्स वैचलर्स और डिप्लोमा कोर्स की डिग्रियां मनमाना शुल्क वसूल कर छात्रों को निर्गत करा रही हैं। इन संस्थाओं में अल्प पारिश्रमिक पर अप्रशिक्षित एवं अपेक्षाकृत अक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति की जा रही है अत इस प्रकार की व्यवस्था से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का ह्रास होना निश्चित है।

(3) निजीकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन– विगत शताब्दी के नौवें दशक में उपयुक्त वातावरण पाकर शिक्षा माफियाओं का आगमन हुआ और पूरी शिक्षा व्यवस्था के समानान्तर एक वित्त आधारित डिग्री व्यवस्था सरकारी शिक्षण संस्थाओं को अपने बाहरी चकाचौंध से एवं आधुनिकता से पिछड़ने का एहसास कराने लगी है फलस्वरूप सरकारी संस्थाओं ने भी कोचिंग सेन्टरों और प्राइवेट कालेजों की तरह वित्त पोषित डिग्रियां बेचना शुरू कर दिया। शिक्षा की गुणवत्ता का आवाज उठाकर आधुनिक उपकरण लगाकर लोगों को आकर्षित करके मोटी रकम वसूल की जाने लगी है। धनाकर्षण के इस मोह ने पूंजीपतियों व व्यवसायियों को निजी शिक्षण संस्थाओं को खोलने पर विवश कर दिया है। इन्हें प्रभावशाली ढंग से रोकने के बजाय यू0जी0सी0 ने सरकारी शिक्षण संस्थाओं को भी स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के माध्यम से कोचिंग सेन्टरों एवं प्राइवेट कालेजों की तरहं शिक्षा व्यापार से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने वाले प्रतिद्वन्दी के रूप में उतारने के लिए लैयार है। भारत के महत्वपूर्ण औद्योगिक घरानों की दृष्टि अब उच्च शिक्षा है। इस दृष्टि का परिणाम है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परियद के दो सदस्यों मुकेश एवं आदित्य बिड़ला द्वारा पॉलिसी फ्रेमवर्क फार रिफार्म्स इन एजुकेशन (Policy Framework for Reforms in Education) नामक प्रतिवेदन 24 अप्रैल 2000 को प्रधानमंत्री को सौपा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार इसे वर्ष 2015 तक की भारत की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है जो कि अपने आप में एक दुःखद विषय है। शिक्षा में सुधार हेतु जहां सुझाव एक समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1948–49) एल0०यस0 मुदालियर (1952–53), डी0एस0कोठारी (1964–66) जैसे शिक्षाविद् करते थे व आज अब उद्योगपति कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में सरकार को उच्च शिक्षा के क्षेत्र से निकल जाने और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्तपोषित बनाने की जोरदार वकालत की गयी है। इन व्यवसायियों की दृष्टि यही नहीं रूंकती वे उच्च शिक्षा को निजी क्षेत्र को सौपने का सुझाव देते हैं। यह समिति शिक्षा को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दिए जाने फी वकालत करती है। साथ ही सरकार को विज्ञान एवं तकनकी प्रबंधन, अर्थशास्त्र वित्तीय प्रबन्धन के क्षेत्र में प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना को संभव बनाने हेतु कानून बनाने का सुझाव देती है। यहां यह तथ्य स्पष्ट होना चाहिए कि भारत का निजी क्षेत्र उच्च शिक्षा की उत्कृष्टता एवं

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

विकास से अधिक अपने विकास के लिए चिन्तित है। देश में इंजिनियरिंग एवं टेक्नॉलोजी के हजारों संस्थानों में से 230 संस्थान ही सरकार फे अधीन हैं पर निजी क्षेत्र की इन संस्थाओं में से किसी भी संस्था का स्तर आई0आई0टी0, आई0आई0एम0, आई०आई0, एम०सी० आदि सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के समकक्ष नहीं है।

(4) स्वायत्तता की उपेक्षा– ज्ञान, मूल्य एवं कौशल का संरक्षण, विकास एवं प्रसार की जिम्मेदारी का भार विश्वविद्यालय पर होता है विश्वविद्यालय ही राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र के लिए नेतृत्व तैयार करते हैं। इन दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन हेतु स्वतंत्रता एक अनिवार्य शर्त है। प्रसिद्ध विचारक पाल गुडमैन (1996) के अनुसार विश्वविद्यालय बुद्धिजीवियों का समुदाय है जो निरन्तर ज्ञान की सीमा बढ़ाने हेतु प्रयासरत रहता है। ज्ञान की सीमा वैचारिक मतभेदों से बढ़ती है वैचारिक भिन्नता विश्वविद्यालय समुदाय के लिए प्राणवायु का कार्य करती है तथा इसी से रचनात्मकता का विकास होता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्वायत्तता आवश्यक है। स्वायत्तता का अर्थ केवल कुलपति या संकयाध्यक्ष को अधिकार सम्पन्न बना देना ही नहीं है स्वायत्तता का तात्पर्य है स्वतंत्रता, दायित्वबोध के साथ। यह स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व का बोध कुलपति से प्रारम्भ होकर कक्षा के छात्र तक पहुंचना चाहिए। तभी विश्वविद्यालय अपने महान उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो सकता है। परन्तु वर्गमान में विश्वविद्यालयी स्वयत्ता पर कई तरफ रो आघात हो रहे हैं।

सरकार ने (NAAC) नेशनल असेसमेन्ट एण्ड एक्रिडिटेशन कोंसिल के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थाओं पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। भविष्य में इस कौसिल के मूल्यांकन के आधार पर ही शिक्षण संरथानों को अनुदान देने की योजना बनायी गई है। सरकार यू0जी0सी0 के माध्यम से विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक स्वतंत्रता समाप्त करने लगी है।

(5) नवउपनिवेशवाद का उदय– भूमण्डलीकरण के दौर में उच्च शिक्षा नवउपनिवेशवाद के गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। आर्थिक वैश्वीकरण ने शैक्षिक वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है। इस प्रक्रिया में औपनिवेशिक काल की पुनरावृत्ति हो रही है। शैक्षिक संस्थाओं के साथ–साथ पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं सोचने की प्रक्रिया भी अमेरिका, यूरोप एवं आस्ट्रेलिया से तृतीय विश्व में निर्यात की जा रही है। विगत कुछ वर्षों में विदेशों के कई विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं ने भारत में प्रवेश किया है। ये प्रायः धन कमाने हेतु आते हैं और देशी एजेण्टों व संस्थाओं से मिलकर मंहगे पाठ्यक्रम चलाते हैं। इस प्रक्रिया को युग्मन (टूविनिंग) कहा जाता है। ये प्रायः पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा देते हैं और शिक्षण सामग्री के नाम पर छात्रों से लाखों रूपये वसूलते हैं। इस सम्बन्ध में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो0 डी0एन0 राव का यह कथन बिल्कुल सही है कि एक अच्छी संस्था के बदले बीस स्तरहीन संस्थाएं देश में आ रही हैं, इनमें कई विदेशी संरथाएं ऐसी है जिन्हें अपने ही देश में मान्यता नहीं मिली है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस शिक्षा व्यापार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारी है। इस प्रक्रिया का गंभीर

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

प्रभाव उच्च शिक्षा पर पड़ रहा है। इन संस्थाओं पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, फलतः शिक्षा का स्तर बनाये रखना असंभव होगा। इनके पाठ्यक्रम इतने मंहगे हैं जो देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या के सामर्थ्य के बाहर है। फलतः ऐसी शिक्षा केवल सम्पन्न वर्ग ही ले पाएंगे, जिससे सामाजिक आर्थिक विषमता बढ़ेगी। विदेशी हितों को पूरा करने वाली शिक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ होगी और युवा वर्ग को राष्ट्रीय संस्कृति से विमुख करने का कार्य करेगी।

(6) बौद्धिक दासता का अर्विभाव– बौद्धिक गुलामी की प्रक्रिया को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से बढ़ावा मिलना निश्चित है इण्टरनेट जैसी सुविधा के विस्तार ने भारत के सुविधा प्राप्त वर्ग की बौद्धिक सोच एवं मानसिक विकास को प्रभावित करना प्रारम्भ कर दिया है। भारतीय विद्वानों, अध्यापकों एवं शोधकर्ताओं में लगातार हीन भावना बढती जा रही है। वे यूरोप या अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय में शोध या अध्यापन कार्य कर भारत में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते हैं। भारतीय अध्यापकों एवं शोधकर्ताओं में आत्मविश्वास की भावना समाप्त होती जा रही है। वे किसी पश्चिमी विश्वविद्यालय में पहुंचकर किसी पश्चिमी विद्वान के अधीन शोध कार्य करके अपनी विद्वता एवं श्रेष्ठता को साबित करते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थाएं इनकी श्रेष्ठता को बिना प्रशन चिन्ह के स्वीकार कर लेती है। इस प्रकार ये पश्चिमी जगत को अपना बौद्धिक नेतृत्व सौंपकर प्रसन्न हो जाती हैं।

निष्कर्ष – उपर्युक्त बातें जो उच्च शिक्षा या उच्च शिक्षा संस्थाओं के बारे में वर्णित की गयी है वे उच्च शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य को दर्शा रही है कि हमारी उच्च शिक्षा किस दिशा में जा रही है? उच्च शिक्षा की तरफ से सरकार भी अपनी जिम्मेदारी सीमित करती जा रही है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न तरह के शुल्क लगातार बढ़ते जा रहे हैं परिणामतः समाज के निम्न वर्ग एवं मध्यम वर्ग के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। निजी क्षेत्र की रूचि उच्च शिक्षा में बढ़ती जा रही है और वे उच्च शिक्षा के क्षेत्र को धन कमाने का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र के रूप में देखने लगे हैं। अनेक विदेशी शिक्षण संस्थाएं अपने शैक्षिक परिसर भारत में स्थापित कर रही हैं, या भारतीय संस्थाओं से मिलकर मंहगे पाठ्यक्रम चलाकर भारतीय छात्रों का शोषण कर रही हैं। ये वैश्वीकरण के नाम पर नवउप–निवेशवाद की वाहक हैं, जो अन्ततः भारत की युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति समाज एवं राष्ट्रीय हितों से विमुख करने की क्षमता रखती हैं।

अतः इन चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को अपनी भूमिका सीमित करने के बजाय संवेदनशील व सार्थक बनानी होगी ताकि अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षा के लाभों से वंचित होने से रोका जा सके। यद्यपि भूमण्डलीकरण ने शिक्षा के बाजारीकरण के खतरे को अनदेखा करते हुए उच्च शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीयकरण की वकालत की है। इस सम्पूर्ण परिदृश्य में प्रत्येक देश को अपनी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक व्यवस्था और तद्नुरूप मौजूदा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भूमण्डलीकरण के स्वरूप का निर्धारण करना

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ तालमेल बिठाते समय राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। शिक्षा मानव के व्यक्तित्व के विकास से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। अतः शिक्षा सम्बन्धी नीतिगत निर्णय लेते समय विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

सन्दर्भ

1–. भारतीय समाज व संस्कृति – रविन्द्र नाथ मुखर्जी

2– भारतीय शिक्षा का विकास – डॉ0 सीताराम जायसवाल

3–. भारतीय शिक्षा का विकास – डॉ0 मालती सारस्वत एवं डॉ0 यल0बी0 बाजपेयी

4– सतत शिक्षा – डॉ0 बी0के0 शर्मा एवं डॉ0 मार्कण्डेय प्रसाद द्विवेदी

5– कल्याण पथ – डा0 मार्कण्डेय प्रसाद द्विवेदी

6– सतत शिक्षा . – डॉ0 शंकर शरण द्विवेदी

7–जच्च शिक्षा मे मूल्यांकन – डॉ0 यरा0एन0 त्रिपाठी

8–उदारीकरण के दौर में उच्च शिक्षा की चुनौतियॉ – डॉ0 नरेश प्रसाद भोक्ता

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies